



# सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

लोरड़ी पण्डितजी, जोधपुर - 342304 (राज.)



क्रमांक: F.4(7)/SPUP/2020-21/Tender/Manpower/Vol.9/ 5037

दिनांक: 16/3/24

## खुली निविदा सूचना-04/2023-24

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के सुव्यवस्थित रूप से संचालन हेतु उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल, अकुशल श्रमिक एवं वि.वि. द्वारा नियत पारिश्रमिक के अनुसार विशिष्ट/अनुभवी कार्मिकों को निविदा के आधार पर उपलब्ध करवाने बाबत ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन-लाइन निविदाएं (02 कवर में) श्रम विभाग से पंजीबद्ध सेवा प्रदाताओं/प्लेसमेन्ट एजेंसी से आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण/सूचनाओं को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> या <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> या <http://www.policeuniversity.ac.in> विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त निविदा के आवेदन हेतु फर्म का अपने डिजिटल हस्ताक्षर (DSC) के माध्यम से वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। निविदा बिना कारण के स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा एवं किसी भी विवाद के मामले में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम होगा।

क्र. सं.	विवरण	संख्या	अनुमानित व्यय	निविदा शुल्क	धरोहर राशि
			(रुपयों में)		
1.	विश्वविद्यालय हेतु उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल, अकुशल श्रमिकों एवं वि.वि. द्वारा नियत पारिश्रमिक के अनुसार विशिष्ट/अनुभवी कार्मिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य।	32 लगभग	40 लाख	500/-	80000/-

निविदा जारी करने एवं आवेदन प्राप्ति की दिनांक तिथि एवं समय :- 19.03.2024 प्रातः 11.00 बजे

निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 02.04.2024 सायं 4:00 बजे

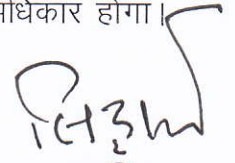
तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय :- 03.04.2024 प्रातः 11:30 बजे

वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय :- यथा समय सूचित किया जाएगा

### निविदा की सामान्य शर्त:-

- वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन निविदाएं ही मान्य होगी।
- निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में दर्शायी गयी प्रक्रिया द्वारा केवल ई-ग्रास के माध्यम से जमा करवाया जाएगा।

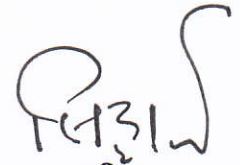
3. निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क के बिना निविदा मान्य नहीं होगी।
4. बिना किसी कारण के न्यूनतम दर अस्वीकृत करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा।
5. शेष नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र में अंकितानुसार यथावत् रहेंगी।



कुलसचिव  
एसपीयूपी, जोधपुर  
दिनांक: 16/3/24

क्रमांक: F.4(7)/SPUP/2020-21/Tender/Manpower/Vol.9/ 5038-44  
प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, एसपीयूपी, जोधपुर
2. वित्त नियंत्रक, लेखा अनुभाग, एसपीयूपी, जोधपुर
3. उप-कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर
4. सहायक कुलसचिव, लेखा अनुभाग, एसपीयूपी, जोधपुर
5. सूचना सहायक, Web Admin, एसपीयूपी को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निविदा को वेबसाइट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in), [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं विभागीय वेबसाइट [www.policeuniversity.ac.in](http://www.policeuniversity.ac.in) पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली
7. Notice Board -कार्यालय हाजा



कुलसचिव  
एसपीयूपी, जोधपुर

## निविदा

एनआईटी सं. (NIT No.)	04 / 2023-24
निविदा जमा करवाने का तरीका	ऑनलाइन <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a> पर e-Procurement/e-Tendering के माध्यम से
निविदा/ सेवा/कार्य	एक वर्ष के अनुबन्ध पर उच्चकुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों एवं वि.वि. द्वारा नियत पारिश्रमिक के अनुसार विशिष्ट/अनुभवी कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु।
निविदा प्राधिकृत / क्रेता	कुलसचिव, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
अनुमानित राशि	40 लाख
निविदा शुल्क	500/-
प्रोसेसिंग शुल्क	500/-
बोली प्रतिभूति राशि/धरोहर राशि	80,000 / -
निविदा जमा कराने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	19.03.2024 को प्रातः 11.00 बजे से
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	02.04.2024 को सायं 04.00 बजे तक
तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	03.04.2024 को प्रातः 11.30 बजे
निविदा/बोली वैधता	120 दिवस (निविदा खोलने की तिथि से)
वेबसाइट (निविदा संबंधी दस्तावेजों, शुद्धिपत्रों एवं परिशिष्टों को डाउनलोड करने हेतु)	<a href="http://www.eproc.rajasthan.gov.in">http://www.eproc.rajasthan.gov.in</a> , <a href="http://www.sppp.rajasthan.gov.in">http://www.sppp.rajasthan.gov.in</a> , <a href="http://www.policeuniversity.ac.in">http://www.policeuniversity.ac.in</a>

बोली प्रतिभूति राशि/धरोहर राशि रु 80000 / -, निविदा शुल्क राशि रु. 500 / - एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि रुपये 500 / - ई-ग्रास की निर्धारित प्रक्रिया (निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न) द्वारा जमा करवाये जाने होंगे।



**--:: निबन्धन एवं शर्तें::--**

इस विश्वविद्यालय के लिए अनुबन्ध पर उच्चकुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों एवं वि.वि. द्वारा नियत पारिश्रमिक के अनुसार विशिष्ट/अनुभवी कार्मिकों की आवश्यकता हैं, जिसके लिए दरें एक वर्ष की अवधि के लिए मांगी गई हैं। इस सम्बन्ध में शर्तें एवं नियम निम्न प्रकार हैं। कृपया दरें निविदा में उल्लेखित शर्तों को पढ़कर दें। बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. निविदा एक वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, राजस्थान लोक उपापन अधिनियम-2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानानुसार अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से 06 माह तक बढ़ाई जा सकती हैं।
2. निविदा शुल्क (राशि रु. 500/-), धरोहर/बोली प्रतिभूति राशि रु. 80,000/- एवं प्रक्रिया शुल्क (500/-) केवल ई-ग्रास की निर्धारित प्रक्रिया (निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न) द्वारा जमा करवाये जाने होंगे।
3. अंतिम तिथि तक निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।
4. निविदा के आवेदन हेतु फर्म का अपने डिजिटल हस्ताक्षर (DSC) के माध्यम से वेबसाइट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
5. निविदा में अंकित दरों में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. डाक द्वारा विलम्ब के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
8. संवेदक को प्रतिदिन 08 (आठ) घंटे सेवा देने के लिए श्रमिक लगाने होंगे एवं उन्हें जहाँ कहीं कार्य करने के लिए कहा जाए वहाँ से नियंत्रण अधिकारी द्वारा नियत समय पर उपस्थित रह कर कार्य करवाना होगा। आवश्यकतानुसार अन्य कार्य करने के लिए भी संवेदक को कहे जाने पर व्यक्ति उपलब्ध करवाने होंगे।
9. दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट एवं साफ अंकित करें।
10. श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मासिक भुगतान अगले माह की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

11. उच्चकुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों एवं वि.वि. द्वारा नियत पारिश्रमिक के अनुसार विशिष्ट/अनुभवी कार्मिकों का बिल प्रत्येक माह की 2 तारीख तक प्रभारी, सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित कराकर प्रेषित करना होगा। बिल में से नियमानुसार आयकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
12. विश्वविद्यालय के आदेशानुसार ही श्रमिक उपलब्ध कराने होंगें, अर्थात् प्रत्येक पारी में श्रमिक 8-8 घन्टें प्रतिदिन के आधार पर लगाए जा सकते हैं।
13. कम्प्यूटर ऑपरेटर (उच्च कुशल श्रमिक) को हिंदी व अंग्रेजी में टंकण आनी चाहिए एवं ऑनलाईन कार्य करने कर पर्याप्त अनुभव हो।
14. अनुबन्धित श्रमिक द्वारा विश्वविद्यालय सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति राशि अनुबन्धकर्ता से वसूल की जायेगी।
15. सफल संवेदक को कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर ₹ 500/- के गैर न्यायिक मुद्रांक (Non Judicial Stamp) पर इकरारनामा पत्र (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्ध राशि की 2.5 प्रतिशत राशि को प्रतिभूति (सुरक्षित) राशि के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करना होगा।
16. अनुबन्ध को बीच में छोड़ने पर जमा प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी एवं अनुबन्ध को शेष अवधि में होने वाले अधिक व्यय नुकसान/हानि की वसूली अनुबन्धकर्ता से की जायेगी।
17. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर, नई निविदा आमंत्रित कर ली जायेगी। स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर मूल अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जायेगी एवं अनुबन्ध की पालना नहीं करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ-साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के तहत तीन वर्ष के लिए बोली लगाने से विवर्जित कर दिया जाएगा।
18. अनुबन्ध की अवधि के दौरान श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जायेगी।
19. संवेदक का यह दायित्व होगा कि आदेश के अनुसार कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल, उच्च कुशल एवं विभिन्न सेवा प्रदत्त अनुभवी मानक के अनुसार उपलब्ध नहीं कराने की अवस्था में कार्य असंतोषजनक मान कर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही प्रेषित कर दी जायेगी।



20. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों का नाम, पता एवं तकनीकी ज्ञान की जानकारी लिखित में विश्वविद्यालय को देनी होगी, जैसे ही कर्मचारी बदला जाये उसकी सूचना मय सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा।
21. कुशल, उच्च कुशल विशिष्ट एवं अनुभवी श्रमिकों को तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक होगा अन्यथा श्रमिकों को अनुबन्ध पर नहीं रखा जाएगा।
22. कार्य दिवस में यदि कोई श्रमिक बिना सूचना अनुपस्थित रहता है तो प्रति श्रमिक रुपये आनुपातिक रूप से प्रति श्रमिक प्रति दिवस विपत्र से कटौती कर दी जाएगी।
23. आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर की कटौती संवेदक को देय राशि में से विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिमाह की जायेगी।
24. संवेदक द्वारा अनुबन्ध आधार पर जो श्रमिक उपलब्ध करवाता है, उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष की रहेगी।
25. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाए गए श्रमिकों में से यदि कोई श्रमिक लगातार 3 दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहता है। तो संवेदक को उसके स्थान पर अन्य श्रमिक उपलब्ध करवाना होगा।
26. संवेदक को ठेका समाप्त होने के तीन माह पश्चात जमा सुरक्षित राशि/कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का भुगतान किया जायेगा यदि उसके विरुद्ध कोई बकाया नहीं हो। किसी भी प्रकार का बकाया होने की स्थिति में बकाया का समायोजन उक्त जमा राशि में से किया जायेगा।
27. संवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा/अण्डरटेकिंग दी जायेगी कि वह पूर्व में किसी विभाग/संस्था/सरकार द्वारा असंतोषजनक कार्य/दुराचरण/दोष सिद्धि के कारण आरोपित नहीं किया गया है तथा न ही ब्लैक लिस्टेड किया गया है।
28. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक निर्धारित समय पर नियत कार्य अनुसार कार्यस्थल पर उपस्थित होंगे एवं संवेदक द्वारा उनकी उपस्थिति बायो-मैट्रिक्स मशीन पर सुनिश्चित करवाकर बिल के साथ संलग्न कर प्रेषित करनी होगी।
29. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक अपने कार्य स्थल को छोड़कर जब तक नहीं कहा जाये अन्य कहीं नहीं जायेंगे।
30. कार्यस्थल अवधि में मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। अभिष्ट व्यवहार करने व कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिये सम्बन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा विश्वविद्यालय के विरुद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
31. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता उत्तरदायी रहेगा।

32. श्रमिकों के पी. एफ. एवं ई. एस. आई. (प्रभावशील होने पर) राशि में पृथक उल्लेख निविदा में करना होगा। पी. एफ. एवं ई. एस. आई. राशि के संबंध में उल्लेख नहीं करने पर श्रम नियमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण राशि जमा करवाने का दायित्व निविदाकार स्वयं का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
33. निविदा के साथ निविदाकार को फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं ई. पी. एफ. का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
34. बोली प्रतिभूति राशि रुपये 80,000/- का ई-ग्रास का चालान संलग्न करना होगा। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
35. निविदा सूचना में अंकित शर्तें निविदा प्रपत्र का भाग माना जाएगा।
36. निविदा प्रपत्र में अंकित निर्धारित शर्तों की पूर्ति एवं प्रपत्र में चाही गई सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर निविदा मान्य नहीं होगी।
37. श्रमिकों के PF एवं ESI जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के अन्त तक प्रस्तुत करना होगा।
38. संवेदक द्वारा दरें एक वर्ष के अनुबंध पर दी जायेगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकार की जाती है, उनके द्वारा उक्त दरों के अनुरूप अनुबंध हस्ताक्षरित किया जायेगा। आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि नियमानुसार बढ़ायी जा सकती है।
39. वि.वि. में निविदा को भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जायेगा।
40. वित्तीय बोली (BOQ) के कॉलम 10 की न्यूनतम दर के आधार पर निविदा अनुमोदित की जाकर संबंधित फर्म को कार्यदेश दिया जायेगा।
41. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
42. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता/संवेदक ही उक्त निविदा भाग ले सकते हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि बोली दस्तावेज के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
43. निविदादाता/संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित निविदादाता/संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण की संतुष्टि होने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
44. श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता/संवेदक का होगा। श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय



पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई राशि न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।

45. बोलीदाता/संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
46. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर **Display Board** लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु **Helpline** नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
47. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
48. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
49. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
50. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के वैधानिक प्रावधानों की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा।
51. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।



52. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने /सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
53. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को **Debar** कराने की कार्यवाही करेगी।
54. निविदा के साथ बोली दस्तावेज 02 कवर में अपलोड किये जायेंगे तथा निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता हस्ताक्षर करेगा।
55. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013 तथा GF & AR की समस्त शर्तें एवं नियम लागू होंगे।
56. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा एवं न्यायिक क्षेत्र केवल जोधपुर ही रहेगा।
57. निविदा की समस्त दरें, निविदा खोलने की तिथि से 120 दिवस हेतु वैध होगी।
58. समय-समय पर राजस्थान सरकार द्वारा जारी समस्त प्रासंगिक आदेश लागू होंगे।

(i). तकनीकी बोली (First Cover - .pdf):

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण/प्रमाण-पत्रों इत्यादि का विवरण संलग्न कर, निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा— अर्हता मापदण्ड (Eligibility Criteria and enclosed certificate duly signed)

क्र. सं.	विवरण	पंजीकरण संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 / संशोधित अधिनियम 2014				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीयन				
5	आयकर (पैन कार्ड नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अन्तर्गत या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत (निविदा की प्रकृति के अनुसार पंजीयन होना आवश्यक है।)				
7	Mandatory Undertaking (बोलीदाता को अनिवार्य रूप से 50 रुपये के गैर-न्यायिक मुद्रांक पर उक्त वचनबद्धता पत्र नॉटरी करवाकर संलग्न करना होगा।)	<b>Bidder should: -</b> <b>a)</b> not be insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and must not be the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons; <b>b)</b> not have, and their directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement/bid contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement/bidding process, or not			



		<p>have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;</p> <p>c) not have a conflict of interest in the procurement/bid in question as specified in the bidding document.</p> <p>d) comply with the code of integrity as specified in the bidding document.</p> <p>e) not have been black-listed by any government or any government statutory agency.</p> <p>f) not sublet the contract, if awarded.</p> <p>g) have submitted only one bid only.</p>	
8	वस्तु एवं सेवा कर (GST) का नवीनतम चुकता प्रमाण पत्र (GST CLEARANCE)		
9	वित्तीय आवर्त (Financial Turn Over) गत 3 वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22, 2022-23 में औसत वार्षिक टर्नओवर 50.00 लाख से कम नहीं हो। (सत्यापन हेतु सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापित अंकक्षित लेखें- लाभ व हानि, बैलेंस शीट आदि संलग्न करने होंगे)	वर्ष	टर्नओवर राशि
		2020-21	
		2021-22	
		2022-23	
10	कार्यानुभव:- गत 3 वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22, 2022-23 में भारत सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धशासकीय संस्थाओं व स्वायत्तशासी संस्थाओं में न्यूनतम 50 मानव संसाधन उपलब्ध करवाने का अनुभव। (कार्यादेश प्रति व सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवाओं के संतोषजनक होने तथा कार्यानुभव की प्रमाणित प्रतियाँ)	वर्ष	मानव संसाधन संख्या
		2020-21	
		2021-22	
		2022-23	
11	Form A, B, C, D with all documents enclosed duly signed by Bidder.		
12	EPF & ESI की ECR (Electronic Challan cum Return) Report कम से कम 50 व्यक्तियों का विवरण हो। (Last Six Months)		

उपरोक्त सूची में संलग्न दस्तावेजों को अपलोड नहीं किये जाने की स्थिति/अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं निविदा को खारिज किया जा सकता है।

(ii). वित्तीय बोली (Second Cover-BOQ.xls) :

संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निम्नानुसार प्रपत्र में BOQ (Excel Sheet) में उद्धृत दरों का विवरण अंकित करना होगा।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि में	कुल राशि (अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित करें) (6+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वि.वि. में सामान्य, तकनीकी एवं विशिष्ट प्रकृति की सेवा	1. अकुशल 2. अर्द्धकुशल 3. कुशल 4. उच्च कुशल 5. उच्च कुशल Man with Machine + विशेष योग्यता 6. वाहन चालक 7. शोध सहायक 8. पुस्तकालयाध्यक्ष	11 .. 8 3  3 1 1	259 271 283 333  9350 (नियत) 14100 (नियत) 20000 (नियत)		13.00%	3.25%		

1. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) राशि नियमानुसार प्रचलित स्लेब के अनुसार अतिरिक्त देय होगी।
2. वित्तीय बोली/प्राईस बिड की तालिका के स्तंभ संख्या 6, 9 व 10 की प्रविष्टि ही बोलीदाता द्वारा ऑनलाईन की जायेगी।
3. बोलीदाता द्वारा स्तंभ संख्या 6, 9 व 10 में शून्य, ऋणात्मक एवं Decimal राशि का अंकन करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. बोलीदाता द्वारा सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
5. ईपीएफ, ईएसआई व वस्तु एवं सेवाकर की राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से देय राशि के अनुसार होगी एवं राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में परिवर्तित दर के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
6. कर्मचारियों की संख्या, पारिश्रमिक एवं कर्मचारियों की श्रेणी में विश्वविद्यालय द्वारा बदलाव किया जा सकता है।

हस्ताक्षर निविदादाता

उपरोक्त सभी शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं, जिससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ एवं मेरे द्वारा दरें सोच-समझ कर दी गई है जिसमें अनुबन्ध की अवधि में मानने को बाध्य रहूंगा एवं सभी नियम एवं शर्तों की पालना करूंगा।

हस्ताक्षर निविदादाता



## घोषणा-पत्र

-

ई-बोली की समस्त जानकारी/शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/ हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं वास्तव में ई-बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा **RPPT** अधिनियम की धारा **46** एवं "नियम" के नियम **39** के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (**Debarred**) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कारवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर किया जा सकेगा तथा ई-बोली को, जिस सीमा तँक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम मय सील

## **Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.**

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

### **Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;
  - a. Have controlling partners/shareholders in common; or
  - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
  - d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:



**Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to .....for procurement of .....in  
response to their Notice Inviting Bids No.....dated .....I/We hereby declare  
under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

## **Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and the address of the first Appellate Authority is, **Registrar, Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice, Jodhpur.**

The designation and the address of the Second Appellate Authority is **Hon'ble Vice-Chancellor, Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice, Jodhpur.**

### **Filing an appeal**

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (1) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (2) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

### **(3) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

### **(4) Form of Appeal**

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.



- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

**(5) Fee for Filling Appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(6) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issued notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
- (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

## **Annexure D: Additional Conditions of Contract**

### **1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

### **2. Procuring Entity's Right to vary Quantities.**

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### **3. Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:  
Place:

Signature of bidder  
Name:  
Designation:  
Address: